लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1 - 15 जुलाई, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 69

"स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।"

: स्वामी दयानंद

अमेरिकी राजमार्गों के समान होंगे प्रदेश के सड़क मार्ग

3

मोरनी में लगेगी सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी परियोजना

4

मनोहर सरकार में रिकॉर्ड विकास

7

सुशासन के लिए नैतिकता

अफसरों के आचरण में नैतिकता व पवित्रता लाने का कार्यक्रम

विशेष प्रतिनिधि

नौकरशाह किसी भी शासकीय व्यवस्था का आधार होते हैं। सूबे का विकास किस राह पर चलेगा और किस गति से चलेगा यह नौकरशाहों की तत्परता पर निर्भर करता है। आम जनमानस कितने सुकून व सहजता के साथ जीवन निर्वहन करता है यह भी नौकरशाहों की निष्ठा, समर्पण एवं मेहनत पर निर्भर करता है।

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, व्यवस्थाएं सुधार की ओर अग्रसर हैं। धीमी कदमचाल की कुछ तो वजह रही होंगी। वे चाहे अज्ञानता की रहीं हों या इच्छा शक्ति की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब पहली बार सूबे की बागडोर संभाली तो संकल्प लिया था कि वे प्रदेश की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, ताकि शासन प्रशासन की उस व्यवस्था को सुधारा जा सके जिसके प्रति लोग निराश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री तब से लेकर आज तक नौकरशाहों के साथ अपने मिशन में जुटे हैं। उनकी अथक व कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज हरियाणा आदर्श प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है।

प्रदेश के साढ़े तीन लाख अधिकारियों व कर्मचारियों के मन में जनसेवा की भावना विकसित करने के लिए अब सामान्य कार्मिक प्रशिक्षण के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि सभी नौकरशाह लोकहित में समर्पित होकर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने के बाद सभी के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि उन्हें समाज सेवा की जिम्मेवारी मिली है। नैतिकता बताई तो जा सकती है लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। यह ऐसा भाव है जिसे जीवन में उतारना पड़ता है। पिछले साढ़े आठ वर्ष के कार्यकाल में उन्हें इस बात का गर्व है कि समाज की सेवा के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जहां से आचरण में नैतिकता व पवित्रता लाने की सोच का कार्यक्रम शुरू हुआ है।

समुद्र का भाव बटोरना, बादल का भाव बांटना

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने नैतिकता के विषय को गीता के श्लोकों के जरिए समझाया। उन्होंने समुद्र और बादल का उदाहरण देकर बताया कि समुद्र नदियों का जल बटोर लेता है लेकिन उसके एक गिलास पानी से इंसान की प्यास नहीं बुझती। वहीं प्रकृति में बरसात देने का भाव छिपा है, जिसके चलते बादलों से बरसने वाली हर बूंद मानवता का कल्याण करती है। रामकृष्ण मिशन के स्वामी सर्वलोकानंद ने कहा कि सुशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही व विश्वसनीयता का होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए निस्वार्थ का भाव नैतिकता की आधारशिला है जो कि मानवीय जीवन का केंद्रबिंदु भी है।

बदलता हरियाणा

सूबे में जब से काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाने लगी हैं तब से परिदृश्य ही बदल गया है। प्रदेश के युवाओं व अभिभावकों को शुरू में मनोहर सरकार की यह योजना जम नहीं रही थी लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया युवाओं की नींद उड़ती चली गई। जिन युवाओं में पढ़ने-लिखने की क्षमता थी वे पढ़ रहे हैं और नौकरी लग रहे हैं तथा जिन युवाओं को पढ़ाई-लिखाई से परहेज था उन्होंने सरकारी नौकरी का सपना छोड़ या तो प्राइवेट सेक्टर में चले गये या अपना काम-धंधा जोड़ लिया। राज्य सरकार केवल पढ़ने वाले बच्चों को ही आत्मनिर्भर नहीं बना रही बल्कि कौशल विकास के साथ स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से आर्थिक मदद भी दिला रही है।

कर्मचारी चयन एजेंसियों के जरिए धड़ल्ले से नौकरियां निकाली जा रही हैं और प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। इनके अलावा किसी अन्य जरिए से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर व विदेशों में रोजगार के लिए भी सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बदलाव के संकल्प का परिणाम यह है कि प्रदेश के युवा पढ़ने लगे हैं। न केवल स्कूल, कालेज व अन्य प्रतिष्ठानों में पढ़ाई हो रही है बल्कि कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरियां भी पढ़ने वाले बच्चों से अटी पड़ी हैं। सच बात यह भी है कि कैरियर की खातिर युवाओं ने विवाह-शादियों से दूरी बना ली है। जीवन में कुछ अच्छा करने की ठान चुके युवा अब पढ़ाई-लिखाई की चर्चा करते हैं, किसी नेता की सिफारिश या पैसे के बंदोबस्त की बात नहीं करते।

प्रदेश में एक नये शैक्षणिक प्रतिस्पर्धात्मक युग की शुरुआत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 8 6,000 नौकरियां दी गई, जबकि वर्तमान सरकार अब तक लगभग 1 लाख 10 हजार नौकरियां दे चुकी है। आने वाले समय में 60,000 से अधिक नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत करीब एक लाख कर्मचारियों को निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में समायोजित किया जा चुका है।

-मनोज प्रभाकर

योगः कर्मसु कौशलम्

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यावाहरिक तौर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। ऐसा होने से किये गए कर्म का परिणाम उत्कृष्ट होता है। योग से न केवल प्रबंधन में कुशलता आती है, जीवन में भी सहजता आती है। प्रासंगिकता की बात करें तो आज के युग में यह जरूरी हो गया है।

योग ऋषियों-मुनियों की धरोहर है, हिन्दुस्तान की विधा है। प्राचीन समय से ही योग की महत्ता रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग की महत्ता को समझते हुए इसे पूरी दुनिया के लिए आवश्यक माना। कहते हैं, युद्ध दुनिया को तोड़ता है और योग दुनिया को जोड़ता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यह जरूरी है कि एक होकर मुकाबला किया जाए व समय रहते उनका निवारण किया जाए।

प्रधानमंत्री की पहल पर योग को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूएनओ के सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन लोगों के साथ योग किया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस साल का थीम 'वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग' रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करवाई थी।

हरियाणा प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए 6500 गांवों में योगशालाएं खोलने का संकल्प लिया गया है, 1000 योग शालाएं तैयार हो चुकी हैं। लगभग एक हजार योग शिक्षकों की भर्ती भी हो चुकी है। योग एवं उसके समकक्ष विद्याओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुरूक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि में आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए कहा है। निजी स्कूलों से भी इसे लागू करने का आह्वान किया गया है।

प्रदेश में योग आयोग की भी स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा है कि योग हमारे जीवन को तनावमुक्त करने का एक साधन है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' लिखा है 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है'। योग के जरिए इसे सही मायने में चरितार्थ करना होगा।

- संवाद ब्यूरो

संपादकीय

हरिहर योजना

हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां बेसहारा बच्चों के लिए यह अनोखी योजना 'हरिहर' शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेसहारा, बेघर या परित्यक्त व आत्मसमर्पित बच्चों का पालन-पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि प्रदेश का हर छोटा बड़ा परिवार आत्मनिर्भर हो। सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिले लेकिन इतनी आय का भी अर्जन हो जिससे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें। किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसी उद्देश्य के साथ समय समय पर रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं जिनमें गरीब परिवार के सदस्यों को फोन करके वहां बुलाया जा रहा है और उनसे उनकी रूचि का कार्य पूछा जा रहा है। इतना ही नहीं बात सिरे चढ़ने के बाद संबंधित बैंक से उनको आर्थिक मदद भी दिलाई जा रही ताकि वे कोई रोजगार शुरू कर सकें।

इन सबके बावजूद भी कुछ लोग रह जाते हैं जो मेलों तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह के परिवारों में वे युवक युवतियां हैं जो अकेले हैं। कुछ ऐसे युवाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में अपने निवास स्थान पर 11 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप-सी व ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्ति दी गई है। 9 लड़कियां व 2 लड़के हैं, जिसमें अदीति, प्रार्थना, माधवी, मधुलिका, नीलिमा, अनादी, सुधा, सरिता, दिव्या, कन्हैया, हिमांशु शामिल हैं।

राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय व रोजगार प्रदान करने के लिए 'हरिहर' नीति अधिसूचित की है। नीति के तहत 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त व एक वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है, जो एक सराहनीय कदम है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

गरीब परिवारों के बच्चे भी बन रहे हैं एचसीएस-आईएएस

जनसंवाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा

प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं जो विकास से अछूता हो, मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रांट भेजते समय कभी किसी सरपंच की पार्टी नहीं पूछी। सभी को विकास के लिए समान ग्रांट दी है।

स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव घोड़ो पीपली, शादीपुर, बलाचौर, फतेहगढ़ व बीबीपुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों के मन की बात सुनी और राज्य सरकार की कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऐसी योजना बनाई है कि अब गरीब का बच्चा भी बिना किसी खर्चे के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अब सरकार की योजना के अनुसार गरीब का बच्चा भी एचसीएस बन सकता है जबकि पहले की सरकारों में नेता के रिश्तेदार या खास परिवारों के लोग इन पदों पर लगते थे। आज पोर्टल के माध्यम से हर आदमी को समान न्याय मिल रहा है। मेरिट में गरीब का बच्चा भी अपनी इच्छानुसार उच्च पद पर पहुंच रहा है।

परिवार पहचान पत्र के साथ विकास संबंधी योजनाओं को जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार आयुष्मान कार्ड, बीपीएल, चिरायु कार्ड व अन्य सुविधाएं मिल रही हैं।

स्वास्थ्य की चिंता

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। आयुष्मान कार्ड से अब गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए चिरायु योजना की शुरुआत की है जो आयुष्मान योजना के अंदर नहीं आते, जबकि पहले केवल 30 हजार रुपए खर्च के लिए कार्ड बनाए जाते थे।

बिजली निगम मुनाफे में

कंवरपाल ने कहा कि 8 साल पहले बिजली में करीब 27 हजार करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था परंतु अब वह घाटा पूरा करके बिजली वितरण विभाग दो हजार करोड़ रुपए के लाभ में है। उन्होंने कहा कि लोगों के करोड़ों रुपए के बिजली सरचार्ज माफ किए और 40 प्रतिशत बिजली का रेट भी कम किया।

हर परिवार हो आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने का वायदा किया है ताकि गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। गांव-गांव अधिकारियों के सहयोग से अंत्योदय मेले लगा कर लोगों से पूछा गया है कि वह कौन सा रोजगार करना चाहते है, पैसा सरकार देगी।

स्कूलों को सुधारा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ड्यूल डैक्स, शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, खेल का मैदान, चारदीवारी व स्कूल में आने-जाने के पक्के रास्ते बनाए गए हैं। जिन स्कूलों की 11वीं कक्षा में 80 से 100 बच्चे थे उन स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। आठ वर्षों में 71 कॉलेज बनाए गए हैं जबकि इससे पहले प्रदेश में 103 कॉलेज थे। अब किसी छात्रा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता।

- संवाद ब्यूरो

बुजुर्ग पेड़ों को मिलेगी 2500 रुपए पेंशन

हरियाणा सरकार बुजुर्ग लोगों को दी जाने वाली पेंशन की तर्ज़ पर 75 वर्ष से ज़्यादा आयु के पेड़ों को भी पेंशन देगी। यह पेंशन 2,500 रुपए प्रतिवर्ष होगी। इस संबंध में सरकार ने द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम तैयार करके अधिसूचित भी कर दी है। अब लोग अपने घर के आंगन में खड़े और खेत में लगे हुए 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों की पेंशन के हक़दार होंगे।

वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने पेड़ों को 'प्राण वायु देवता' की संज्ञा देते हुए कहा कि पेड़-पौधों से ही हमें जीवन-रक्षक ऑक्सीजन मिलती है, अगर हम सचेत नहीं हुए तो पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन की उपलब्धता मुश्किल हो जाएगी।

योजना को राज्य के लोगों के लिए जीवनदायिनी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वैसे तो सभी पेड़ पौधों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है परन्तु 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ अपने फैलाव के कारण अधिक ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए सरकार ने इन बड़े पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नई स्कीम बनाई है। इस स्कीम में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ शामिल नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर खड़े पेड़ इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

विमानन सेवा: उड़े देश का आम नागरिक

गुरुग्राम-हेलीपोर्ट राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको जल्द शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हिसार एयरपोर्ट से देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए हवाई यात्रा आरंभ की जाएगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम -हेलीपोर्ट से संबंधित अधिकारियों द्वारा सुझाई गई विभिन्न साइट्स के बारे में चर्चा की और जल्द से जल्द इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

उन्होंने उड़ान योजना के तहत हिसार एयरपोर्ट से शुरू किए जाने वाले रूट्स की चर्चा करते हुए कहा कि हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, आदमपुर देहरादून, गोरखपुर, जयपुर, अमृतसर, कुल्लू, जम्मू समेत अन्य शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू किए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल, 2017 को नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख कार्य म क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत टियर-2 और टियर-3 शहरों में उन्नत विमानन संरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ 'उड़े देश का आम नागरिक' की परिकल्पना के बाद आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुई थी।

उड़ान के तहत पूरे देश में 220 गंतव्यों (हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/वाटर एरोड्रोम) को वर्ष 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश के बिना संपर्क वाले गंतव्यों को हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना ने भारतीय विमानन उद्योग के परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब रेल परिवहन और सड़क परिवहन के साथ-साथ नागर विमानन हरियाणा में परिवहन का आधार बन जाएगा।

- संवाद ब्यूरो

हरियाणा सरकार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, उमरी, कुरुक्षेत्र को तीन एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करेगी। एनआईडी के पास 23 एकड़ का परिसर क्षेत्र हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी जिले के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

अमेरिकी राजमार्गों के समान होंगे प्रदेश के सड़क मार्ग

सोनीपत में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में नितिन गडकरी बोले

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि दिसम्बर, 2024 तक हरियाणा में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य होगा। इन परियोजनाओं से हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और हरियाणा के सड़क मार्ग अमेरिका के सड़क मार्गों के समान होंगे।

केन्द्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने 890 करोड़ रुपए की दिल्ली से पानीपत तक एनएच-44 पर 8 लेन के 11 फ्लाईओवर्स का लोकार्पण किया, जिसमें दोनों ओर 6 लेन की सर्विस रोड भी शामिल है।

नितिन गड़करी ने कहा कि दिसम्बर 2024 तक उनका मंत्रालय हरियाणा में 100 प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। जिनमें से 2200 किलोमीटर की 47,000 करोड़ रुपए की 51 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 756 किलोमीटर की 20,000 करोड़ रुपए की 19 अन्य परियोजनाएं हैं जिनमें 14 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ काम टेंडर प्रक्रिया में है।

नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लिए आरओबी व आरयूबी के निर्माण हेतु 'सेतू भारतम' योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की रखी गई मांग को मौके पर ही मंजूरी प्रदान की।

काम करना मोदी सरकार की विशेषता

नितिन गडक़री ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था जो थोथा निकला।

उन्होंने कहा कि 60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, उससे भी दोगुना काम केवल 10 साल में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करके दिखाये, यही हमारी सरकार की विशेषता है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। जनधन योजना में गरीबों के 49 करोड़ बैंक खाते खोले गए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मुद्रा योजना में व्यवसाय करने के लिए 40 करोड़ लोगों को बैंकों से माइक्रो 'क्रेडिट और मुद्रा लोन की सुविधा दी। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर दिये। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा स्कीम का फायदा मिला। जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 14 करोड़ लोगों को बीमा कवर मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में 12 करोड़ जल कनेक्शन दिए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 32 योजनाओं के द्वारा देश के करीब 100 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ देने का काम किया और गरीब, मजदूर व किसान के साथ-साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।

ई-रिक्शा से एक करोड़ लोगों का जीवन हुआ आसान

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, मेरा मानना है कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के अगर सबसे अच्छे कामों के बारे में बात की जाए तो उसमें एक बात यह होगी कि एक करोड़ लोग, जो रिक्शा चलाते थे। उनको एक बड़ी राहत देते हुए ई-रिक्शा दी गई। आज कोई पीठ पर बोझा नहीं ढोता। आत्मनिर्भरता का अहसास होता है।

कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है हरियाणा सरकारः मनोहरलाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साढ़े 8 सालों से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई इबादत लिखी है। सड़क और रेल तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योजनाओं को लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि 10 साल पहले सभी जानते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की सरकार थी। हमने इन बुराईयों को जड़ से समाप्त किया है। इन साढ़े 8 सालों में निडर होकर सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना किसी पर्ची-खर्ची के, बिना भेदभाव के मिशन मैरिट पर सरकारी नौकरियां दी। आज युवा शिक्षा की ओर अग्रसर है।

सबसे ज्यादा नौकरियां दीः मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 8 6,000 नौकरियां दी गई। जबकि हमारी सरकार अभी तक 1 लाख 10 हजार नौकरियां दे चुकी है और 60,000 नौकरियां पाइप लाइन में हैं। इस प्रकार हमारी सरकार के 10 साल पूरे होने पर नौकरियों की संख्या 1,70,000 हो जाएगी।

करनाल में रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1690 करोड़ रुपए की करनाल ग्रीनफिल्ड 6 लेन रिंगरोड परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन करनाल के कुटेल गांव में हुआ। गडकरी ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि करीब 1700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 35 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। यह रोड करनाल के एनएच-44 पर शामगढ़ से शुरू होकर बड़ौता गांव तक होगी। इससे न केवल करनाल शहर की भीड़ कम होगी बल्कि वाहनों को चलाने की लागत भी कम होगी।

गडकरी ने कहा कि देश का किसान अन्नदाता है उसे अब ऊर्जादाता बनने की जरूरत है। पानीपत में इंडियन ऑयल ने पराली से एक लाख टन बायो एथनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन उद्योग शुरू किया है। अब आगे बिटुमिन की जगह बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं। हवाई जहाज में 2 प्रतिशत बायो एविएशन फ्यूल डालने का कानून बना है। हम 16 लाख करोड़ का फोसिक फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसान की गरीबी गेहूं, चावल और गन्ना उत्पादन से दूर नहीं होगी बल्कि किसान को ऊर्जादाता बनना होगा। एक नए युग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। आज मक्के व बांस से एथनॉल बनाया जा रहा है। गन्ने के जूस से एथनॉल बन रहा है। किसान को इसके लिए आगे आना चाहिए और ऊर्जादाता की भूमिका निभानी चाहिए। किसान एथनॉल और सीएनजी बनाएगा तो 16 लाख करोड़ रुपए जो इम्पोर्ट पर खर्च किया जा रहा है, उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसान की जेब में आएंगे तो किसान समृद्ध होगा।

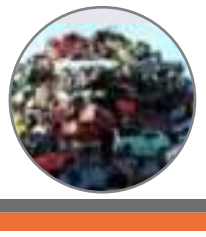

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से 1 अप्रैल, 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश हुए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था व औद्योगिक विकास के दृष्टिगत कम विकसित 'सी' व 'डी' श्रेणियों के ब्लॉकों में हरियाणा कृषि-व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मेरा पानी, मेरी विरासत

किशाऊ, लखवार व रेणुका बांधों की परियोजना सिरे चढ़ाने की पहल

हरियाणा के खेत कभी प्यासे न रहें, उन्हें भरपूर सिंचाई जल उपलब्ध होता रहे तथा जनजीवन को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल निरंतर मिले इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि जल संरक्षण के प्रति इतनी गंभीरता बरती जाए कि आने वाली पीढ़ी को जल संकट की समस्या का सामना न करना पड़े।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस योजना के अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे।

योजना के तहत धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसल की ओर जाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। परिणाम यह है कि 1.5 लाख एकड़ भूमि पर किसानों ने धान की बजाय अन्य फसलों को तरजीह दी है। ऐसे किसानों को 7 हजार प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान के स्थान पर अन्य फसलों के अधीन ले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, अब किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की बचत होगी।

एक जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20 लाख 93 हजार 598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर हुआ। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कार्य योजना से अगले दो वर्षों के इस अंतराल को पूरा किया जाए। इनपुट के आधार पर द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023-25) तैयार की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए तीन कमेटियां गठित की गई हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई वर्षों से लंबित जल संरक्षण की किशाऊ, लखवार व रेणुका बांधों की परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने की पहल की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के केंद्र सरकार से किये गए आग्रह पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मंच पर आये और आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर किये। किशाऊ को तो बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना घोषित किया गया है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने सिंचाई व जल संसाधन क्षेत्र को 6598 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है ।

एसवाईएल का पानी हिमाचल के रास्ते पानी लाने पर विचार

एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है। उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है फिर भी हिमाचल के रास्ते लाने के एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया गया है। योजना का खाका हिमाचल को भेजा गया है। सिंचाई विभाग (मिकाडा सहित), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायत विभाग, तालाब प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, वन, शिक्षा इत्यादि विभागों को भी जल संसाधन के कार्यों में सहयोग देंगे ताकि जल बचाओ अभियान को सफल बनाया जा सके।

-मनोज प्रभाकर

मोरनी में लगेगी सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी परियोजना

शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त 'क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई।

बैठक में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और मिकाडा के कुल 4 एजेंडा रखे गए थे और सभी एजेंडे को मंजूरी दी गई। विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग एक करोड़ 41 लाख रुपए की बचत की गई है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट

मोरनी खण्ड में टपरिया, कंडियावाला, कैंबवाला, खैरवाली परवाला और लश्करीवाला गांवों के लिए सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इंफिल्ट्रेशन गैलरी बनाई जाएगी, जिससे साफ पानी को आगे भेजा जाएगा। पाइपलाइन तथा कुहल के माध्यम से पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाएगा। जहां सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

इंदौरी नदी का होगा जीर्णोद्धार

गुरुग्राम जिला में गांव बास पदमका से सिवारी तक इंदौरी नदी का जीर्णोद्धार की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर लगभग 20 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, सिंचाई विभाग की लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की एक ओर परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत लाखन माजरा लिंक ड्रेन पर वीआर पुलों का पुनः निर्माण किया जाएगा। आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

- संवाद ब्यूरो

सब्जी उत्पादन पर पांच हजार रुपए सब्सिडी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर गन्नौर स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी केवल ईंट-सीमेंट का भवन मात्र नहीं, अपितु किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मददगार साबित होगा। यह हरियाणा के किसानों के साथ फल व सब्जी उत्पादकों, आम लोगों तथा व्यापारियों के लिए ख़ासी लाभकारी सिद्ध होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्यों के किसान-व्यापारी मंडी का लाभ उठा सकेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2,600 करोड़ रुपए के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया। मंडी में दूसरे चरण के कार्यों में करीब 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

इनमें 495 लाख रुपए की लागत से भिवानी में बनाई जाने वाली सब्जी मार्केट, 1,204.03 लाख की लागत से भिवानी के सिवानी में नई अनाज मंडी का निर्माण, 894.94 लाख रुपए की लागत से करनाल के असंध में मूनक खरीद केंद्र को सब यार्ड विकसित करने, सिरसा में 2,481.38 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी, अनाज मंडी व लक्कड़ मंडी के विकास के लिए अतिरिक्त मंडी, 192.56 लाख की लागत से कंवरपुरा गांव में खरीद केंद्र का निर्माण तथा 224.47 लाख रुपए की लागत से शेरपुरा गांव में खरीद केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

राज्यों के किसान-व्यापारी मंडी का लाभ

यह भारत ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनेगी। इससे उत्तर भारत के राज्यों के क्रेताओं-विक्रेताओं को विशेष लाभ मिलेगा। दिल्ली की आजादपुर मंडी के बेहतरीन विकल्प के रूप में यह मंडी तैयार होगी, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया होंगी। मंडी किसानों की आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगी। हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मज़बूती मिलेगी।

सब्ज़ी उत्पादकों को मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों के लिए घोषणा की कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को तीन वर्षों के लिए पांच हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल गन्नौर खंड में तीन हजार एकड़ में सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें और वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नौ वर्षों में किसानों का जितना भला वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किया है उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया।

कुरूक्षेत्र में सुरजमुखी का तेल कारखाना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुरजमुखी उत्पादक किसानों के लिए कुरुक्षेत्र में चार एकड़ भूमि में तेल का कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 20 हजार मिट्रिक टन की होगी। सुरजमुखी के बीज से तेल व घी का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय आगामी वर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।

-संवाद ब्यूरो

दिव्यांगजन की सहायता के लिए जल्द ही राज्य में हेल्प डेस्क सेंटर खोले जाएंगे। जहां से वह सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ अपनी समस्याएं भी दर्ज़ करवा सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से च्लेन ड्राइविंग और अंडर ऐज ड्राइविंग का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान लेन ड्राइविंग के 3176 और अंडर ऐज ड्राइविंग के 258 चालान हुए।

मशरूम उत्पादन से रोज़गार

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में मशरूम उत्पादन तकनीक विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण में हरियाणा प्रांत के विभिन्न जिलों जैसे हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, करनाल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी के प्रशिक्षणार्थियों ने भी भाग लिया।

मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम लागत में शुरू किया जा सकता है। भूमिहीन, शिक्षित एवं अशिक्षित युवक व युवतियां इसे स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं तथा सारा वर्ष भी मशरूम की विभिन्न प्रजातियों जिनमें सफ़ेद बटन मशरूम, ओयस्टर या ढींगरी, मिल्की या दूधिया मशरूम, धान के पुवाल की मशरूम इत्यादि उगाकर सारा साल मौसम के हिसाब से इसका उत्पादन किया जा सकता है। सरकार द्वारा भी किसानों तथा बेरोजगार युवाओं को इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मशरूम एक संतुलित आहार है इसमें कई तरह के पौष्टिक तथा औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके नियमित सेवन से मनुष्य में रोगों एवं विकारों से बचाव में सहायक होती है। मशरूम उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चिता के साथ-साथ वायु प्रदूषण से भी निजात मिलेगी।

अभी हाल ही में हरियाणा में 21500 मैट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ, जिसमें लगभग 99 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन सफेद बटन मशरूम का ही है। दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ के अलावा कई अन्य छोटे बड़े शहरों के साथ-साथ गावों में भी इसकी मांग बनी रहती है और इसको बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है।

- संवाद ब्यूरो

धान की पराली से आमदनी

एक समय था जब हरियाणा में धान की पराली को पर्यावरणीय खतरे के रूप में देखा जाता था लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे किसानों की आय बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में बदलने का काम किया है। सरकार ने पराली के सदुपयोग व सही प्रबंधन के लिए सामान्य निर्धारित दर की घोषणा की है। इसके अंतर्गत धान की खेती में इन-सीटू और एक्स-सीटू तकनीक और डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ धान की पराली के लिए 2,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन के कॉमन डिटरमाइंड रेट की घोषणा जैसे उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, हरियाणा ने पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करने में सफलता हासिल की है। इस तरह, ये प्रयास सतत कृषि पद्धतियों के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह बात धान की पराली जलाने की घटनाओं से निपटने संबंधी एक बैठक में कही। बैठक में राज्य की कार्य योजना और तैयारियों की समीक्षा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष एम.एम. कुट्टी, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी.राघवेंद्र राव और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक नरहरि बांगर उपस्थित थे। सभी उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।

किसानों को वित्तीय सहायता

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में शून्य कृषि अग्नि परिस्थिति के लक्ष्य को प्राप्त के लिए राज्य सरकार ने 2,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन एवं 20 प्रतिशत से कम नमी पर अतिरिक्त 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन रुपए की सीडीआर अधिसूचित की है। इसके अलावा, हरियाणा किसानों को रुपए सहित वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन-सीटू/एक्स-सीटू तकनीक के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपए और 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत 7,000 प्रति एकड़ और धान की खेती में डीएसआर तकनीक के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपए निर्धारित है। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए किसानों को उनकी आय अधिकतम करने में सहायता करना है।

आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष एम. एम. कुट्टी ने कहा कि हरियाणा ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम की प्रशंसा है, लेकिन पराली जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस दिशा में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं ताकि पराली का उचित प्रबंधन हो सके। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए आईओसीएल पानीपत में स्थापित इथेनॉल प्लांट में पराली पहुंचाने के लिए आस-पास के जिलों के किसानों को ज़ागरूक किया जाए। किसानों को पराली को जलाने के बजाय इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को पराली के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर आयोग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

गुणकारी तुलसी की पैदावार व देखभाल

तुलसी पौधा हिंदू संस्कृति में आदर्श एवं पूजनीय माना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी को धार्मिक, आयुर्वेदिक और वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है।

राम तुलसी : यह प्रमुख तुलसी का प्रकार है। हिंदू धर्म में इसकी खास मान्यता है। इसकी पत्तियों का गहरा हरा रंग होता है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है।

श्यामा तुलसी : यह भी महत्वपूर्ण तुलसी का प्रकार है, पूजा में इसे उपयोगी माना जाता है। पत्तियों का रंग गहरा हरा या श्याम होता है।

वाणी तुलसी : इस तुलसी का ग्रीन टी और वनस्पति विज्ञान में उपयोग होता है। इसकी पत्तियां बड़ी और मोटी होती हैं।

बन तुलसी : बन तुलसी को जंगली तुलसी के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियां छोटी और वृद्धि करने वाली होती हैं। यह आमतौर पर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है

लॉग तुलसी : इसकी पत्तियां बड़ी और मोटी होती हैं। इसकी खुशबू भी अत्यंत सुंदर होती है। लॉग तुलसी को आमतौर पर औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यह खांसी, सर्दी, जुकाम, पाचन, त्वचा संबंधित रोगों और श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने में फायदेमंद होती है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा: तुलसी को आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह वात, पित्त और कफ को शांत करके शरीर के रोगों को ठीक करने में मदद करती है। तुलसी की चाय और तुलसी का रस शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पाचन क्रिया को सुधारते हैं और इम्यून सिस्टम को मज़बूत करते हैं।

तुलसी पौधे की स्पेसिंग को अच्छी तरह से प्लान करें। यह आपके वातावरण और उगाने के लिए उपलब्ध स्थान के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

बागवानी के लिए, आमतौर पर तुलसी की बटाई की जाने वाली दूरी 12-15 इंच होती है। इसके अलावा, यदि आप तुलसी का संग्रहण करना चाहते हैं, तो 8-10 इंच की दूरी पर बटाई की जा सकती है।

तुलसी पौधे में उर्वरक प्रबंधन

» तुलसी पौधों को नियमित रूप से खाद्य पुष्टि प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
» उर्वरक का उपयोग करने से पहले पौधों को पानी से संतुलित रखें। यह सुनिश्चित करेगा कि उर्वरक संचयित होकर पौधों के रोटसिटम को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।
» उर्वरक के रूप में कम्पोस्ट खाद, निम्बू का रस, अम्लीय उर्वरक, खाद्य पाउडर या औषधीय उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं।
» पौधों को उर्वरक देने की सिफारिश किया जाता है जब पौधे की संग्रहण शुरू होती है और हर 15-20 दिनों के बाद नियमित अंतराल पर उर्वरक देना चाहिए।
» आमतौर पर, तुलसी पौधों को उर्वरक की प्रति पौधे दर 15-20 ग्राम रखा जाता है। इसे हर 15-20 दिनों के बाद नियमित अंतराल पर देना चाहिए।

कीट प्रबंधनः

मक्खी और मक्खीटरी को पौधे से दूर रखने के लिए प्लास्टिक की शील्ड या मैट का उपयोग करें। यह उन्हें प्रवेश नहीं करने देगा।

» छिपकली को भगाने के लिए पौधे के आस-पास नींबू के छिलके का प्रयोग करें। छिपकली इसकी गंध को पसंद नहीं करती है।
» यदि कीटों की संख्या अधिक हो जाए, तो उचित कीटनाशक का उपयोग करें। लेकिन सुनिश्चित करें कि यह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और संशोधित मात्रा में ही प्रयोग करें।
» पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लक्षणों को ध्यान से निगरानी करें। यदि रोग पाया जाता है, तो सबसे पहले प्रभावित इलाके की पत्तियां हटा दें। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम साफ फफूंदनाशक का प्रयोग करें।
» बैक्टीरियल ब्लाइट रोग को नियंत्रित करने के लिए कोपर दवा का उपयोग करें। इसे पौधे के लंबे समय तक नियमित रूप से स्प्रे करें।
» फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए पौधे की अच्छी संगठनात्मक देखभाल करें। पानी को पत्तियों पर नहीं छोड़ना चाहिए और पत्तियों को सुखाने के लिए धूप में रखें। पोटेशियम बाइकार्बोनेट युक्त कवकनाशी का छिड़काव करके पत्ती के धब्बे को नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रस्तुतिः अनिल कुमार (कृषि विज्ञान केंद्र, यमुनानगर) ममता खेपड, मोनिका जांगड़ा (वानिकी विभाग), प्रीति वर्मा (पौध रोग विभाग) चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सीएफएमएस की लंबित फाइलों के निपटान के लिए कहा है कि इन फाइलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाया जाए। महीने में एक दिन समीक्षा बैठक होगी।

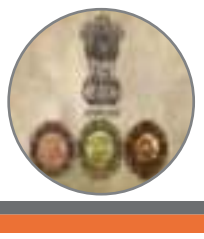

पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रदेश वासियों को 10 हजार रुपए मासिक पेंशन तथा राज्य सरकार की वोल्वो बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

हरियाणा में खत्म हुआ इन्सपेक्टरी राज

व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। वर्तमान राज्य सरकार भी व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है।

पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इन्सपेक्टरी राज को खत्म करने का काम किया। प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि जब देश में जीएसटी को लागू किया गया तब व्यापारियों के मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया। आज व्यापारी इस सिस्टम से बेहद खुश हैं।

सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को अब एकमुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2 प्रतिशत मार्केट फीस व 2 प्रतिशत एचआरडीएफ की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है।

प्रदेशभर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी।

सरकारी गोदाम शहर से बाहर शिफ्ट होंगे

प्रदेशभर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की।

मानधन योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना हीं नहीं, पीएम-स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

-संवाद ब्यूरो

ऑनलाइन बिक्री के लिए बनेगा पोर्टल

मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए की बड़ी घोषणाएं

संगीता शर्मा

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की देखरेख में चल रहे सेल्फ़ हेल्प ग्रुप एक सोशल हेल्प ग्रुप के रूप में महत्वपूर्ण भूमिा निभा रहे हैं। इस मिशन से जुड़ी महिलाओं को सराहनीय कार्यों व समाज में योगदान देने के लिये विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।

गुरुग्राम के चंदू गांव की क्षितिज़ स्वयं सहायता समूह की पूजा शर्मा मोटे अनाज के बिस्कुट, नमकीन व अन्य उत्पाद बनाकर बेचती हैं। उनका कहना है कि समूह से जुड़कर अधिक महिलाओं को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह समूह से पैसे उठाते हैं और उनकी किस्तों में वापिस करती हैं इससे उनका परिवार में दर्जा भी बड़ा है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए नई घोषणाओं से महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और वह समूहों में जुड़ने में रूचि दिखाएगी।

रोहतक के लाखन माजरा गांव के प्रगति स्वयं सहायता समूह की मानता शर्मा हैंडब्लॉक प्रिंटिंग व स्क्रीन पेंटिंग की साड़ी, सूट, दुपट्टे, चादर, पिल्लो कवर, कुश कवर, गुदड़ी, बैग व अन्य ज़रूरत के सामान की बेचती है। वह बताती है कि वह अपने उत्पादों की बिक्री मेले के साथ-साथ ऑनलाइन बेवसाइट के माध्यम से भी करती है। वह कहती है कि अब हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा पोर्टल बनाने से ऑनलाइन सामान की बिक्री अधिक हो सकेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा स्वयं सहायता समूह की नई घोषणाओं से महिलाओं को लाभ मिलेगा।

महेंद्रगढ़ के बवानिया के प्रतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह की प्रधान भागवंती देवी का कहना है कि राशन डिपो के लिए दी जाने वाली स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता और बस स्टैंड में दी जाने वाली दुकान के लिए प्राथमिकत का विषय बहुत ही सराहनीय है। इससे सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का व आर्थिक रूप से मज़बूत बनने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड में दी जाने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्य को एक साल के लिए विशेष छूट भी बहुत ही प्रशंसनीय काम है।

उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता को सर्टिफाई कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने उत्पादों के निर्माण में एसएचजी नवीनता लाएं और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की ओर भी विशेष ध्यान दें। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों व समाज में योगदान देने के लिये विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। जिला गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी पूजा शर्मा को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ी

प्रदेश में लगभग छह लाख महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि वे समाज की सच्ची ताकत हैं। प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। वर्ष 2014- 15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2,100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और साढ़े आठ साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवोल्विंग फण्ड, लगभग 28 5 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फण्ड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवोल्विंग फंड की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है।

- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

कई बड़ी घोषणाएं

- राशन डिपो अलॉट में उनमें 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं को देने का निर्णय।
- पंचायत की ज़मीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करने पर उन्हें नीलामी की राशि में दस प्रतिशत की छूट।
- बस स्टैंड पर लॉटरी या किसी अन्य तरीके की दुकाने के आवंटन पर 25 प्रतिशत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित। नीलामी की राशि में दस प्रतिशत की छूट।
- यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से अधिक बढ़ती है तो एक वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं कटेगा।
- एक पोर्टल बनाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी, ब्रांडिंग व बिक्री।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की प्रर्िया के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

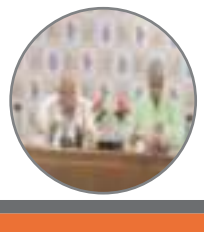

उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई है।

मनोहर सरकार में रिकॉर्ड विकास

अमित शाह बोले, हरियाणा में नौ साल पहले चलती थी थ्री डी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा में रिकॉर्ड विकास हुआ है। देश का सबसे पहला कैरोसीन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी-लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015 से 2022 तक 6 प्रतिशत से ज्यादा रही है। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी।

सिरसा रैली में अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक राज्य को 5.22 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में हैं। 50 प्रतिशत गाड़ियां हरियाणा में बनती हैं। हमारी सरकार ने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनाए। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए। 20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई। 12,150 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल नूह जिलों से गुज़रने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया। 11,000 करोड़ की लागत से खरखौदा में 10 लाख वाहन की क्षमता का प्लांट विस्तारीकरण का काम हुआ।

उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपए मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 30 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा है। 82 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बने हैं।

शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है। वरना इनसे पहले हुड्डा के कार्यकाल में थ्री डी की सरकार चलती थी। थ्री-डी यानी दरबारी, दामाद और डीलर। मनोहर लाल ने इन तीनों डी को समाप्त कर दिया है। 10 साल कांग्रेस की सरकार में जितना धान व गेहूं खरीदा गया उससे कहीं ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। वर्ष 2014 से 2022 तक 260 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 385 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। 47 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में गए है।

- संवाद ब्यूरो

अंत्योदय परिवारों का सहारा बनी दयालु योजना

हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना, ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए, की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली दो लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपए किया जाए।

मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।

वर्तमान में दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

- संवाद ब्यूरो

फेसलेस सेवाओं से बढ़ेगी पारदर्शिता

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को पारदर्शी व नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और राज्य के समग्र विकास और कल्याण में योगदान देना है। इसी मकसद से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ किया। यह सेवा डिजिटल सशक्तिकरण व नागरिकों की सुविधाओं की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम है। जो हरियाणा के नागरिकों को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साहिब होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फेसलेस सेवाओं का ब्रोशर भी लॉंच किया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवाओं का लाभ आवंटी अब व्यक्तिगत रूप से एस्टेट कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना कहीं से भी उठा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म 2437 सुलभ है, जिससे नागरिक आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। फेसलेस सर्विस के शुभारंभ से हरियाणा के नागरिकों को कई लाभ होंगे और आवंटी अब विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे स्थानांतरण अनुमति पत्र, नॉन डयूज प्रमाण पत्र, गैर-भार प्रमाण पत्र, इंडिपेंडेंट तल-स्थानांतरण अनुमति पत्र, मोर्टगेज अनुमति पत्र, इंडिपेंडेंट तल पुर्नआवंटन पत्र, डी-मोर्टगेज अनुमति पत्र, स्थानांतरण अनुमति रद्द करना, आवंटन पत्र (ई-नीलामी) और पुनः आवंटन पत्र की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

पशुओं की चिकित्सा देखभाल एवं पशुपालकों की सुविधा हेतु 70 मोबाइल पशु वैन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

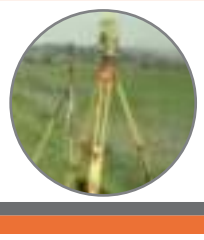

हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को गति देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 300 जीएनएसएस रोवर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।

तनाव मुक्त जीवन के लिए आवश्यक योग

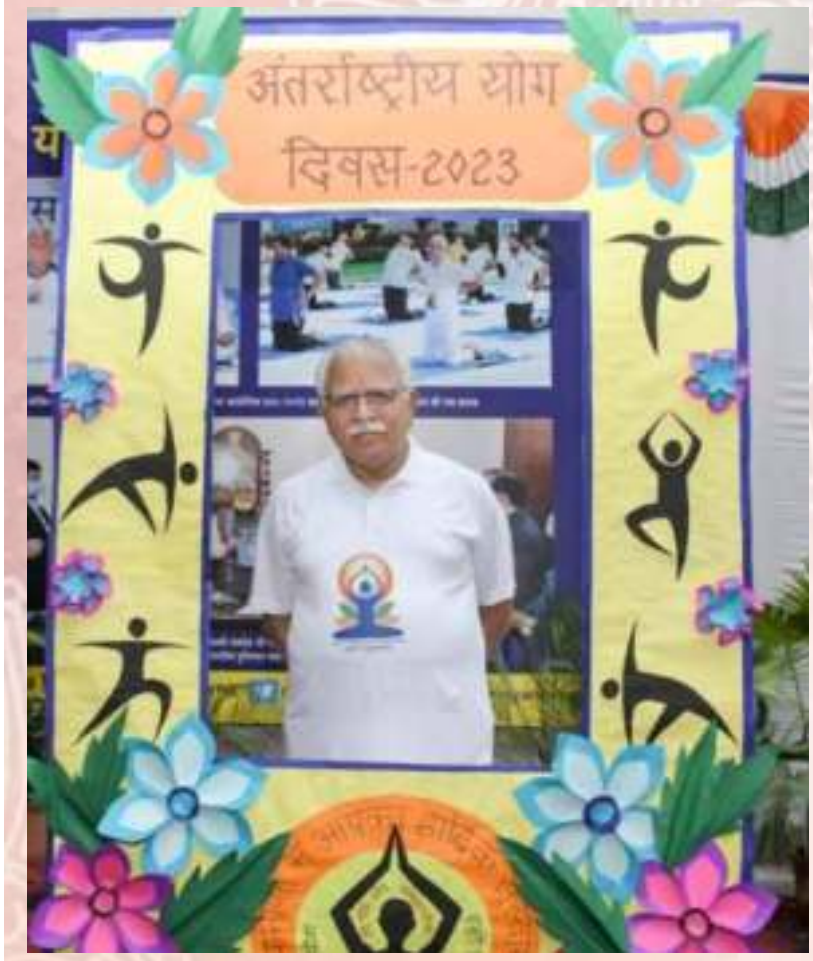

योग स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था को सुदृढ़ करने का मूल मंत्र है। वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि योग के जरिए जीवन को सहज व सरल बनाए रखा जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करवाई थी। इस वर्ष उन्होंने योग को विश्व के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम् के लिए योग' को शीर्ष वाक्य देकर जी-20 समूह के देशों को भी मानव जीवन में योग के महत्व का संदेश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि स्कूल से ही योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे रोज लगभग 45 मिनट योग एवं व्यायाम करते हैं। योग करने से व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है।

हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया और विभिन्न योगों के लाभ बताए। आयुष विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए तुलसी का पौधा और श्रीमद्भागवत गीता भेंट कर सम्मानित किया।

पंचकूला में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योग को केवल योग-दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हम सभी प्रण लें कि योग को जीवनशैली के सुधार एवं मन की एकाग्रता के लिए इसे अपनाते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि योग ऋषियों-मुनियों की धरोहर है। प्राचीन समय से ही योग की महत्ता रही है। योग हिंदुस्तान की विधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस विधा को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया है।

श्रम राज्यमंत्री अनूप धानक ने प्रदेश कहा कि यदि हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम इस जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। यह योग से संभव है।

गुरुग्राम जिला में 'हर घर आंगन योग' थीम के तहत अंतरराष्ट्रीय योग दिवस गरिमामयी ढंग से मनाया गया। सेक्टर-38 के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित समरोह में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व योगाभ्यास किया।

रोहतक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ.कमल गुप्ता ने कहा कि हर व्यक्ति योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाये ताकि वह स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। व्यक्ति के फेफड़ों में लगभग 14 करोड़ सैल मौजूद है। सामान्य सांस लेने में केवल तीन से चार करोड़ सैल ही सक्रिय रहते हैं, इसलिये योग आवश्यक है।

जगाधरी में शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनने का मूल मंत्र है। योग स्वस्थ जीवन जीने की एक पद्धति है। जींद में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग पूरे विश्व में फैला हैं, यह भारत के लिए गर्व की बात है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा योग के प्रचार-प्रसार के लिए योग आयोग का गठन किया गया है।

- संवाद ब्यूरो

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है तथा यह दिल दिमाग और शरीर को एकता के सूत्र में पिरोने काम करता है, एकाग्रता एवं अनुशासन की भावना पैदा करता है। योग करने से व्यक्ति मन और आत्मा से भी स्वस्थ रहता है।

उन्होंने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग भारत की एक प्राचीन सफल विद्या है तथा स्वस्थ जीवन जीने की एक शानदार कला है। योग के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं को अध्यात्मिकता से जोड़कर जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्जवलित करके आगे बढ़ सकता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाएं।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com